भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4210

29 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए नियत

ऑटोमोबाइल क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन

4210. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

डॉ. जयंत कुमार राय:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऑटोमोबाइल/परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्यौरा क्या है;

(ख) सीओपी-26 में भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ऑटोमोटिव उद्योग की तैयारियों को ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में ऑटोमोटिव/परिवहन क्षेत्र को हरित बनाने के लिए कोई प्रयास कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) से (घ): प्रदूषण-रहित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. भारी उद्योग मंत्रालय ने देश में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) के अंगीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहन का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम 2015 तैयार की। वर्तमान में, फेम इंडिया स्कीम के चरण-II को कुल 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 01 अप्रैल, 2019 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों में कमी के लिए हेतु देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के निर्माण हेतु 18,100 करोड़ रूपये के बजटीय परिव्यय से उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को दिनांक 12 मई, 2021 को मंजूरी दी।

iii. ऑटोमोबिल और ऑटो घटकों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से दिनांक 15 सितंबर, 2021 को पाँच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था। इस स्कीम में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन सेलचालित वाहनों के लिए 18 प्रतिशत तक का प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

******